



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1996]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2010/आश्विन 6, 1932

No. 1996]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2010/ASVINA 6, 1932

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2010

का.आ. 2347(अ).—अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं.का.आ. 451 (अ) द्वारा 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन, अंतर्राज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था ;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय 1 अप्रैल, 2007 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करें ;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को और बढ़ाने का समय-समय पर अनुरोध किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं० का०आ० 400(अ) तारीख 20 मार्च, 2007 का०आ. 414 (अ.) तारीख 3 मार्च, 2008, का०आ० 2116 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 01 अप्रैल, 2009 तक बढ़ा दिया था ;

और कर्नाटक सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से रिट याचिका 408/2008 द्वारा निवेदन किया कि वह केन्द्रीय सरकार को फरवरी या मार्च, 2006 को अधिकरण के गठन की तारीख के रूप में निश्चित करने के लिए निर्देश दें ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसम्बर, 2008 को मामले की सुनवाई की और निर्देश दिया कि अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन कृष्णा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 1 फरवरी, 2006 होगी।

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 1 फरवरी, 2009 से प्रभावी एक वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था ;

और न्यायालय के आदेश, अधिसूचना सं० का० आ० 2116(अ) तारीख 27 अगस्त, 2008 तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना सं० का० आ० 543(अ) तारीख 25 फरवरी 2009 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 1 फरवरी 2009 से प्रभावी एक वर्ष की एक और अवधि के लिए 31 जनवरी 2010 तक बढ़ाया था ;

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट विनिश्चय की प्रस्तुति करने की अवधि को 1 फरवरी, 2010 से प्रभावी आठ मास की एक और अवधि के लिए पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं० का० आ० 212(अ) तारीख 29 जनवरी, 2010 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को 30 सितम्बर, 2010 तक की अवधि के लिए बढ़ाया था ;

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुत करने की अवधि को 1 अक्टूबर, 2010 से 2 माह की और अवधि के लिए बढ़ाने का पुनः अनुरोध किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति करने की अवधि को 30 नवम्बर, 2010 तक के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 17/1/2007-बे. प्र.]

जी. मोहन कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2010

S.O. 2347(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on 2nd April, 2004 *vide* notification number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And Whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under Sub-section (2) of section 5 of the said Act on or before the 1st day of April, 2007;

And Whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for further periods from time to time;

And Whereas, the Central Government *vide* notifications number S.O. 400(E), dated the 20th March, 2007, S.O 414 (E), dated the 3rd March, 2008, S.O. 2116 (E), dated the 27th August, 2008 had extended the period of submission of report and decision upto 1st April, 2009;

And Whereas, the Government of Karnataka approached Hon'ble Supreme Court *vide* Writ Petition 408/2008 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as February or March 2006;

And Whereas, the Hon'ble Supreme Court heard the matter on 17.12.2008 and directed that effective date of the constitution of the Krishna Water Disputes Tribunal under section 3 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, would be 1st February, 2006;

And Whereas, the said Tribunal again had requested to extend period of submission of its report and decision for a further period of one year with effect from 1st February, 2009;

And Whereas, after taking into consideration the Court order, the notification number 2116(E), dated the 27th August, 2008 and the proviso to sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government *vide* notification number. S.O 543 (E), dated the 25th February, 2009, extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 1st February, 2009 upto 31st January, 2010;

And Whereas, the said Tribunal had again requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of eight months with effect from 1st February 2010;

And Whereas, the Central Government *vide* notification number S.O 212(E), dated the 29th January, 2010 had extended the period of submission of report and decision upto 30th September, 2010;

And Whereas, the said Tribunal has again requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of two months with effect from 1st October 2010;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the said Tribunal upto 30th November, 2010.

[F.No. 17/1/2007-BM]

G. MOHAN KUMAR, Addl. Secy.